



राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

The Love Story of Iqbal, Hasrat Jaipuri

The 'City of Witches'

Centuries ago, it was said that Benevento was a gathering place for the occult. Today, superstitions still run deep

Marilyn Monroe and the Potato Sack Dress

महिला आरक्षण को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है सरकार

इस सोच के तहत संसद में तीन दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, 16 से 18 अप्रैल को

-नेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। संसद के बजट सत्र में एक तीसरा विशेष सत्र देखने को मिलेगा, जिसे 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बुलाया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सके।

लोकसभा और राज्यसभा को आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थगित कर दिया गया, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं।

दोनों सदन की 16 अप्रैल को फिर से बैठक होगी, जहां सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक पेश करेगी।

महिलाओं को आरक्षण देने की अपनी मंशा का संकेत देने की जल्दबाजी में सरकार इसे परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना से जोड़ना चाहती है, जो अब पुरानी हो चुकी है

इस मकसद से सत्र में विशेष संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। हालांकि, अभी सरकार के सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, पर फिर भी सरकार इस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए अड़ी हुई है।

सरकार का मानना है कि अगर विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मैसैज तो जाएगा ही, कि सरकार महिला आरक्षण के पूर्णतया पक्ष में है। पर, विपक्ष सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दे रहा है।

क्योंकि, विपक्ष, इस दौरान विधानसभा चुनाव में व्यस्त होगा। अतः सरकार की सोच है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने का पूरा नाटक वह आसानी से रच सकेगी।

और इसका कोई खास औचित्य नहीं माना जा रहा है।

अन्य संशोधन भी प्रस्तावित है,

लेकिन राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना आसान नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

भले ही यह पूरा मामला एक राजनीतिक नाटक साबित हो और विधेयक पारित न हो, पर सरकार यह प्रचार जारी रख सकती है कि वह विधेयक पास करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था।

यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।

इस बीच, विपक्षी दल विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और भाजपा इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक खींचतान और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।

एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

जयपुर, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में एसआई भर्ती, 2021 में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतर्गम राहत दी है। अदालत ने इन्हें अस्थाई तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को राहत दी।

परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। जस्टिस दीपाकर दत्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को कहा है कि वे अदालती आदेश की कॉपी 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराएं और वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें।

प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात जजों को नौ घंटे बंधक बनाकर रखा गया बंगाल के मालदा जिले में

ये जुडिशियल अफसर एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य कर रहे थे

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक बनावट में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है।

मालदा जिले के मोथाबाडी क्षेत्र में एक घटना सामने आई, जिसमें एसआईआर कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देर रात केन्द्रीय बलों की एक टुकड़ी ने मौके पर पहुंचकर इन अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ये घटनाएं उसी तरह हो रही हैं, जैसा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से करने का आ

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि बंगाल में हर चीज का "राजनीतिकरण" हो चुका है। अतः सवाल यह उठ रहा है कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश में बढ़ती अराजकता व हिंसा के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही।

ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से हिंसा प्रतीपादित कर रही हैं तथा कह रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने देंगे।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन जुडिशियल अफसरों ने राज्य सरकार को और कोलकाता हाई कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया, अपनी सुरक्षा के बारे में, विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ कि सत्यापन का काम कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की भारी भर्त्सना की, इन जुडिशियल अफसरों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करने के कारण। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर जुडिशियल अफसरों को ही सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो निष्पक्ष, निडर, चुनाव होने की संभावना की कल्पना ही व्यर्थ है।

कह रही है। बताया गया कि महिलाओं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह लवली युनिवर्सिटी के चीफ अशोक मित्तल की नियुक्ति की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी लाइन का उत्सर्जन करने के कारण राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक-चेयरमैन हैं।

गुरुवार को आप की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया, जिसमें पार्टी के उपनेता पद के लिये पंजाब से निर्दिष्ट चुने गए मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया।

मित्तल ने मीडिया से कहा, "हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का समय मिलता है; यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राघव चड्ढा को भी भविष्य में राज्यसभा में बोलने का अवसर दिया जाएगा।"

आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर मित्तल की नियुक्ति की सूचना दी गई तथा पत्र में राघव चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखने का आग्रह भी किया गया है।

आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव काफी समय से पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी के वॉकआउट के समय भी वे सदन में बैठे रहते थे, यही नहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भी दूरी बना ली है।

चर्चा है कि राघव भाजपा नेतृत्व के समर्थक भी हैं। इसलिए आप ने पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली युनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया है।

आप ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखा जाए। सूत्रों के अनुसार, 37 वर्षीय चड्ढा पिछले कुछ महीनों में कई बार सदन में

पार्टी लाइन के खिलाफ जाते रहे हैं। 12 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिस पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वृद्धा से 80 लाख की साइबर ठगी करने वाले की अग्रिम जमानत से इंकार

जयपुर, 2 अप्रैल (निर्स)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 80 लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नवीन टेमानी की ओर से

हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जो समझौते से सुलझाया जा सके।

दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे समझौते से सुलझाया जा सकता है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गंभीर अपराध है, अदालत ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'5037 बीघा में कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, नक्शा बनाकर पेश करो'

हाई कोर्ट में 5037 बीघा ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 2 अप्रैल। राजस्थान

हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में अवाप्त की जा रही 5037 बीघा जमीन में से काफी बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में 'पब्लिक अगेन्सट करप्शन' नामक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश पुष्पेन्द्र पाटी और पुनीत कुमार माथुर ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ए.एस.जी.) के आश्रय को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिये हैं कि राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि एक

भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेंगा। अदालत ने आदेश में आगे कहा कि हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता के वकील पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से रोका जा सके।

याचिकाकर्ता, "पब्लिक अगेन्सट करप्शन" ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि 12 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही है, 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

हाउसिंग बोर्ड ने कहा, कुल अवाप्त 5037 बीघा जमीन में से 4000 बीघा पर हमारा कब्जा है, शेष 1037 बीघा जमीन पर कुछ जरूरतमंदों ने कब्जा कर रखा है।

अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका यह कहते हुए दायर की गई है कि 12 मार्च 2025

को अदालत ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान

एसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया है कि 5037 बीघा में से 4000 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की जा चुकी है और उसका कब्जा है। शेष भूमि पर कई जगह अतिक्रमण है, परंतु वह इसलिए है कि जयपुर में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है और बाहर से आये लोगों को शहर में बसाने के लिये गैरकानूनी कॉलोनियां काटी गईं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण रोकना अत्यंत ही मुश्किल काम है। हालांकि गैरकानूनी सोसायटी काटने से सुनियोजित विकास नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकारों को शहर के बाहर से आये गरीबों और रोजगार की खोज में आये लोगों की आवश्यकताओं को भी देखना जरूरी है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से इस मुद्दे पर संवेदनशील करना चाहा कि अतिक्रमण हटाने से कई गरीबों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईपैक के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की रेड

बेंगलुरु, 02 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चोटिंग से पहले एक बार फिर से आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में यह कार्यवाही चल रही है। इससे पहले कोलकाता स्थित ऑफिस में ईडी की रेड हुई थी। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल

आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव प्रबंधन संभाल रही है और यह रेड कोयला तस्करी के मामले में की जा रही है।

को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थीं। इस दौरान खूब सियासी बवाल हुआ था।

दरअसल, ईडी की यह छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में चल रही है। आईपैक पश्चिम बंगाल में टोपमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 2 अप्रैल। प्रदेश में अदालती आदेशों के बावजूद स्वायत्तशासी ग्रामोण व शहरी निकायों के चुनाव समय पर आयोजित नहीं कराये जाने के खिलाफ, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर नाराजगी जताते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता ने प्रदेश के निर्वाचन आयोग समेत, मुख्य चुनाव अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिये।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जब अदालत यह तय कर चुकी है कि 15 अप्रैल से पहले निकायों के चुनाव आयोजित किये जाने हैं तो निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम को स्वतः ही आगे कैसे बढ़ा सकता है, जबकि

अदालती आदेश के बावजूद चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी स्वायत्तशासी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें।

परंतु अदालती आदेशों के बावजूद मुख्य निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी करे, जिसके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और फिर उसका अंतिम प्रकाशन होगा और चुनाव उसके बाद ही हो सकेगा।

अदालत ने इसकी न तो कोई अनुमति दी है, और न ही अदालत से अनुमति मांगी गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी पैरवी

के लिये प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी

2026 तक प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिये थे कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी

कर ली जाये। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव आयोजित नहीं कराने की वजह से कई निकाय गैरकानूनी तरीके से अपने कार्यकाल से डेढ़ से दो वर्ष अधिक से कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं आयोजित होने की वजह से आम जनता के वोट डालने के संविधानिक हक को छीना जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आदेश दिये थे कि 15 फरवरी तक चुनाव करा दिये जायें।

पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि अदालती आदेशों के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी किये, जिनके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और उसका अंतिम प्रकाशन हो जायेगा। उन्होंने अदालत को कहा कि ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक चुनाव आयोजित कराने के आदेश की पालना असंभव है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और टिप्पणी की कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईआरजीसी कमांडर फतह अलीजादेह की मौत

तेहरान, 02 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ईरान को एक और झटका लगा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली फतेहिन स्पेशल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली फतह

ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई।

अलीजादेह की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

स्वयं को बदल दो, भाग्य बदल जायेगा -कहावत

एक जिला एक उत्पाद नीति राजस्थान : लोकल टू ग्लोबल

राजस्थान की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। राजस्थान, जो अपनी रंगीन संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, इस नीति के माध्यम से आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचानना और उसे बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने इसे तुरंत अपनाया और 2021 से राज्य स्तर पर इसे लागू किया। राजस्थान सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। राज्य में 33 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक प्रमुख उत्पाद चुना गया, जो स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और बाजार क्षमति पर आधारित है। उदाहरणस्वरूप, बाड़मेर का लेहरीया मिठ, जोधपुर का मोतीकारी कढ़ाई, जयपुर का हस्तशिल्प, उदयपुर का मिनि एकर पेंटिंग और अलवर का मोर पंख शिल्प इनकी बाणी भर है। ये उत्पाद न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि राजगार सुजन के खाते भी बन रहे हैं।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टिगत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

ODOP के तहत राजस्थान के जिलों ने अपनी विशिष्टताओं को निखारा है। बाड़मेर में लेहरीया और बंधेज साड़ियां अब दुबई और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच रही हैं। यहां 500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनका उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा। जोधपुर का ब्लू सिटी अब मोतीकारी फनीचर के लिए जाना जाता है। सरकार ने यहां ODOP क्लस्टर विकसित किया, जहां डिजाइन वर्कशॉप आयोजित होती हैं। जयपुर का ब्लू पॉन्टी और कोमती पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिला। अलवर के हस्तशिल्प और दोसा के आंबला उत्पाद ने वैश्विक खेती को प्रोत्साहित किया। कोटा का कोटा स्टोन और बांसवाड़ा का बांस उत्पाद भी चमक रहे हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे स्थानीय संसाधन वैश्विक अवसर बन रहे हैं।

यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं,

मजबूत आधार है। राजस्थान रिस्कल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RSLDC) ने 10,000 से अधिक कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को जोड़ा गया। उदाहरण के लिए, उदयपुर के बांसवाड़ा में आदिवासी महिलाओं को बांस उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर बाजार से जोड़ा गया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। सरकार ने जौड़ाई ग्रैंड आवेदन तेज किए, जैसे बाड़मेर का बंधेज और कोटा का डोरिया साड़ी को मान्यता मिली। यह ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ।

चूनातियां भी हैं, जिन्हें सरकार दूर करने में जुटी है। कच्चे माल की कमी, बाजार पहुंच और तकनीकी पिछड़ापन प्रमुख हैं। रेगिस्तानी जलवायु में रंगाई-प्रक्रिया प्रभावित होती है, इसलिए सोलर ड्रायर और वाटर हार्वोस्टिंग योजनाएं शुरू की गईं। डिजिटल साक्षरता के अभाव को दूर करने हेतु मोबाइल वन भेजी जा रही है। कोवडि-19 के बाद सप्लाय चेन बाधित हुई, लेकिन ODOP ने इसे अवसर में बदला परिणामस्वरूप, 2023-24 में ODOP से 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। 50,000 से अधिक राजगार सृजित हुए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

ODOP ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया है। पीढ़ियों से चली आ रही कला, जैसे जोधपुर की साफा बांधन कला या चित्तौड़गढ़ की ततवार नक़्काशी, अब विलुप्त होने के कगार से लौट रही है। युवा पीढ़ी को जोड़ने हेतु स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। यह नीति सतत विकास का प्रतीक है, जहां पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। जैविक रंगों का उपयोग और प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग से ग्रीन ब्रांडिंग हो रही है। वैश्विक स्तर पर सरटेनेबल हैडीक्राफ्ट की मांग में राजस्थान अग्रणी है।

भविष्य की योजनाएं उत्साहजनक हैं। सरकार 2026 तक 10,000 करोड़ का निर्यात लक्ष्य रख रही है। ODOP पार्क विकसित हो रहे हैं, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एआई और ब्लॉकचेन से ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उत्पाद की प्रामाणिकता बनी रहे। स्टार्टअप इंडिया से जोड़कर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सप्तेद्वारियों, सैंडे जपान और यूरोप के ब्रांड्स के साथ, नए द्वार खोल रही है। राजस्थान का ODOP मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है।

एक जिला एक उत्पाद नीति ने राजस्थान को साबित कर दिया कि स्थानीयता वैश्विकता का आधार बन सकती है। यह न केवल आर्थिक उन्नति ला रही है, बल्कि सांस्कृतिक गौरव को भी पुनर्जीवित कर रही है। कारीगरों की मुस्कान, ग्रामीणों की समृद्धि और राज्य की प्रतिष्ठित इस्की साक्षी है। लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार हो रहा है, और राजस्थान इसकी आगुवाई कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह नीति भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा देगी।

—अतिथि संपादक,

अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

राशिफल शुक्रवार 3 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2083, चित्रा नक्षत्र सायं 7:25 तक, व्याघ्रात योग दिन 2:08 तक, कौलव करण प्रातः 8:43 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 6:24 से तुला राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मीन, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मेघ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
 आज राजयोग प्रातः 8:43 से सायं 7:25 तक है। आज एकलिंगजी पाटोत्सव उदयपुर में है। आज गुड फ्राडे है।
श्रेष्ठ चौघडिया: चर सूर्योदय से 7:52 तक, लाभ-अमृत 7:52 से 10:58 तक, शुभ 12:30 से 2:05 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:41

मेघ
परिवार में प्रसन्नता-हार्दोल्लास बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर संधिगत आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही रुद्धि दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

दिन में बिजली और सौर ऊर्जा क्रांति से सशक्त होता किसान



पुष्येंद्र सिंह राणावत

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी संकल्प लेकर इसे तेजी से क्रियान्वित करवा रहे हैं। दोसा एवं करौली जिले के कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ करने के साथ ही अब कुल 24 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली सुलभ करावा जा रही है।

अब जयपुर डिस्ट्रिक्ट के 9 जिलों—जौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डींग, दोसा, करौली एवं भरतपुर में बिजली सुलभ करने के लिए 52,460 तथा करौली जिले के 35,341 कृषि उपभोक्ता अब दिन में बिजली आपूर्ति का उपभोग कर सकते हैं।

कृषकों को इन जिलों में कड़ाके की सर्दी एवं बारिश में रात्रि के समय सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इन 24 जिलों में दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में, बेहतर निगरानी के साथ अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने वाले जिलों में हो रहे निरन्तर विस्तार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।



सुनील दत्त गोयल

भारत में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों युवा अपनी उम्र के सबसे उत्पादक वर्ष इस तैयारी में लाग देते हैं— कोचिंग, किराया, किताबें, परीक्षा शुल्क और सबसे बढ़कर मानसिक दबाव— इन सबका बोझ उठाते हुए यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का एक लंबा संघर्ष बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अंततः न्यायपूर्ण अवसर में बदलता है, या फिर एक ऐसी प्रणाली में फँस जाता है जहाँ प्रतिभा हारती है और सिस्टम चुक जाता है?

आज की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि सरकारी भर्ती प्रणाली धीरे-धीरे एंटी सिस्टम बनती जा रही है। न गति करियर सिस्टम न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं होने के बावजूद, चपरासी, क्लर्क और लोअर ग्रेड की नौकरियों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएसए और एमबीबी जैसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों का उद्देश्य उस पद पर स्थायी रूप से कार्य करना नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह सरकारी तंत्र में प्रवेश लेना होता है, ताकि आगे चलकर वे बेहतर पदों के लिए प्रयास कर सकें। यहाँ से शुरू होती है वह समस्या, जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला

चिताड़गढ़ एवं डूंगरपुर तथा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 जिलों—जालौर, सिराही एवं पाली में भी कृषकों को दिन के दो ब्लॉक में आपूर्ति का रहा है।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए दोसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके साथ ही दोसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एम्पीवी की क्षमता वृद्धि की गई है। करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एम्पीवी की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दोसा जिले के 52,460 तथा करौली जिले के 35,341 कृषि उपभोक्ता अब दिन में बिजली आपूर्ति का उपभोग कर सकते हैं।

कृषकों को इन जिलों में कड़ाके की सर्दी एवं बारिश में रात्रि के समय सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इन 24 जिलों में दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में, बेहतर निगरानी के साथ अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने वाले जिलों में हो रहे निरन्तर विस्तार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इस परिवर्तन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत किए गए विद्युत ढांचे की है। नए ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना, ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि और वितरण नेटवर्क के विस्तार ने इस योजना को व्यवहारिक रूप दिया है। राज्य सरकार ने नीति बनाकर इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी तैयार की है।

इस पूरी पहल का सबसे सशक्त आधार केवल पारंपरिक बिजली आपूर्ति नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा के रूप में उभरती नई शक्ति है। पीएम-कुसुम योजना में यह बदलाव को गति दी है और राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। राज्य में अब तक लगभग 1961 मेगावाट क्षमता के 940 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश पिछले दो वर्षों में ही पूरे हुए हैं। राजस्थान ने अब सूर्य की ऊर्जा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। कुसुम योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने किसान की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। किसान केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि वह ऊर्जा उत्पादक भी बन गया है। खेतों में लगे सोलर पेणों के माध्यम से किसान दिन में सिंचाई कर रहा है, डीजल पर उसकी निर्भरता समाप्त हो रही है और उत्पादन लागत कम हो रही है। अतिरिक्त बिजली को दिन में बेचकर किसान आय का एक नया स्रोत भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, अनदाता अब ऊर्जादाता के रूप

में भी उभर रहा है।

इस परिवर्तन का राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संरचना पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली सीधे स्थानीय ग्रिड से जुड़ने के कारण ट्रांसमिशन लाइंस में कमी आई है और बिजली वितरण अधिक प्रभावी हुआ है। लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। महंगे थर्मल पावर पर निर्भरता घट रही है और स्वच्छ ऊर्जा का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जल संसाधनों पर दबाव कम हो रहा है और वायु प्रदूषण घट रहा है। यह योजना केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त माध्यम है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सोलर संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव ने नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं। युवाओं को तकनीकी क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गतिशीलता आई है। अब खेती फसल उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन के साथ बहुआयामी गतिविधि बन चुकी है।

राज्य सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कई नवाचार किए हैं। सौर

संयंत्रों की स्वीकृति, ऑनलाइन एपीएम, मीटर टेस्टिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया गया है। वन-स्टॉप समाधान प्रणाली ने किसानों और निवेशकों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाया है। इससे परियोजनाएँ तेजी से धरतल पर उतर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सामान गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति, तकनीकी रखरखाव, किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण और सौर परियोजनाओं के विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो राजस्थान में दिन में बिजली आपूर्ति और पीएम-कुसुम योजना के समन्वय का मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार के बेहतर समन्वय से राजस्थान अब प्रगति के नये सोंपन अर्जित कर रहा है। अब राजस्थान का किसान अंधेरे में संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि उजले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किसान बन रहा है। खेतों में फसल के साथ ही ऊर्जा भी उमर रही है और यही एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान की पहचान है।

—पुष्येंद्र सिंह राणावत,
विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री

सरकारी भर्ती में कट ऑफ से आगे की कहानी : जहां प्रतिभा हारती है और सिस्टम चूकता है

कर रही है— जाँइन-टैन-छोड़ संस्कृति। एक अभ्यर्थी पहले एक पद ग्रहण करता है, फिर कुछ महीनों या वर्षों में दूसरे, अधिक आकर्षक पद पर चयनित होकर उसे छोड़ देता है। यह अब अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित प्रवृत्ति बन चुकी है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग होता है, जिससे कई पिछली सीटें अनावश्यक रूप से खाली हो जाती हैं।

ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों का सपना सिर्फ आईएएस बनने का होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन आईपीएस, आईआरएस या अन्य अधीनस्थ सेवाओं में होता है, तो वो उसको भी खोइने कर लेते हैं और बाद में वह बार-बार आईएएस की परीक्षा देते रहते हैं और जब अंत में उनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी तमना पूरी होने पर वो पिछला पद छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक ही वजह से पिछली सीटें खाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं, कायदे में जिंको वे रह पुरानी सीट मिलनी चाहिए थी। यदि हम आधिकारिक अंतर्कर्मियों को देखें, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। संसद में प्रस्तुत हालिया आर्कडों के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 9.6 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। कुछ स्वतंत्र विश्लेषणों में यह संख्या 10 लाख के आसपास भी बताई गई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और अन्य नौकरियों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएसए और एमबीबी जैसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों का उद्देश्य उस पद पर स्थायी रूप से कार्य करना नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह सरकारी तंत्र में प्रवेश लेना होता है, ताकि आगे चलकर वे बेहतर पदों के लिए प्रयास कर सकें। यहाँ से शुरू होती है वह समस्या, जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला

भर्ती में देरी नहीं, बल्कि पकेट-सेलेक्शन अस्थिरता का स्पष्ट संकेत— जब कोई उम्मीदवार चयनित होता है, तो सरकार उस पर प्रशिक्षण, वेतन, आवास और अन्य सुविधाओं के रूप में लाखों रुपये खर्च करती है। कई मामलों में यह खर्च प्रति उम्मीदवार 2 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक होता है। उच्च सेवाओं में यह लागत और भी अधिक होती है। यह पैसा करदाताओं का होता है। लेकिन जब वही उम्मीदवार कुछ समय बाद सेवा छोड़ देता है, तो यह पूरा निवेश संकलनात्मक बन जाता है— जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता।

इससे भी बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब वह सीट खाली रह जाती है और उसी भर्ती को प्रतीक्षा सूची को सक्रिय नहीं किया जाता। यह स्थिति डेड सीट कहलाती है— जहाँ पद मौजूद है, जबरन मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जिला स्तर पर इसका असर बेहद गंभीर होता है— स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, प्रशासन में अधिकारी नहीं— और इसका सीधा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। यहाँ लास्ट कट-ऑफ की अवधारणा पूरी तरह सवालियों के घेरे में आ जाती है। कट-ऑफ एक तकनीकी सीमा है, लेकिन जब चयनित उम्मीदवार सेवा में नहीं टिकते और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता, तो यह कट-ऑफ न्याय नहीं, बल्कि अन्याय का उपकरण बन जाती है। जो उम्मीदवार केवल कुछ अंकों से पीछे रह गए थे, वे केवल इसलिए बाहर रह जाते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें अवसर देने में विफल रहता है। यह न केवल प्रतिभा का नुकसान है, बल्कि सिस्टम की नैतिक विफलता भी है। इस पूरी समस्या को यदि कार बिंदुओं में समझें, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है—

(1) एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग
 (2) सरकारी संसाधनों— वेतन, प्रशिक्षण, सप्ताह— का दुरुपयोग
 (3) प्रतीक्षा सूची के योग्य उम्मीदवारों को अवसर न मिलना
 (4) चयन प्रक्रिया में देरी और रिक्त पदों की बढ़ती संख्या

अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? और क्या केवल सुधार से काम चलेगा या एक कठोर नीति की आवश्यकता है? सबसे पहला और सबसे प्रभावी समाधान है— रोलिंग वेटलिस्ट प्रणाली का अनिवार्य क्रियान्वयन। इसका सिद्धांत बेहद सरल है— जिस भर्ती वर्ष की सीट खाली होती है, उसे उसी वर्ष की प्रतीक्षा सूची से 12-18 महीने के भीतर भर दिया जाए, यह कोई जटिल सुधार नहीं है, बल्कि एक बुनियादी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो डेड सीट की समस्या लगभग समाप्त हो सकती है और अंतिम कट-ऑफ से थोड़ा पीछे रह गए उम्मीदवारों को वास्तविक न्याय मिल सकता है। लेकिन केवल रोलिंग वेटलिस्ट पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार एक कठोर और स्पष्ट नीति ढांचा तैयार करे। उदाहरण के लिए— जब कोई अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी पद के लिए आवेदन करे, तो वह यह लिखित घोषणा दे कि वह उसी पद के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके साथ ही न्यूनतम सेवा बॉन्ड (3-5 वर्ष) लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार सेवा अवधि से पहले सेवा छोड़ता है, तो उससे प्रशिक्षण और अन्य खर्चों की वसूली की जाए। इसी तरह, क्रॉस-सर्विस परीक्षाओं के लिए सीमित प्रयास और कूल-ऑफ अवधि भी तय की जानी चाहिए, ताकि उम्मीदवार बिना जिम्मेदारी के बार-बार सिस्टम का उपयोग न कर सकें। नीति-निर्माण के स्तर पर पारदर्शिता भी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में डेटा बिखरा हुआ है— कितने पद भरे गए, कितने उम्मीदवारों ने जाँइन नहीं किया, कितनों ने सेवा छोड़ी, कितनी सीटें खाली रह गई— इन सभी का समीकृत और नियमित प्रकाशन नहीं होता। यदि यह डेटा सार्वजनिक रूप से

उपलब्ध हो, तो न केवल समस्या का सही आकलन हो सकेगा, बल्कि नीति-निर्माण भी अधिक डेटा-आधारित और प्रभावी होगा। इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण नैतिक आयाम भी है, जिसे अवसर नजर अंदाज कर दिया जाता है। क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति अपने करियर के लिए बार-बार अवसर ले और फिर छोड़ दे, जबकि कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार उसी अवसर के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा हो? यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि उन उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय है, जिन्हें लिए वह नौकरी अंतिम लक्ष्य

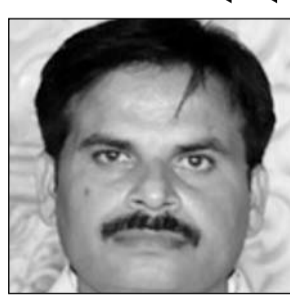
था। यदि कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसे सीधे उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि अन्य पदों को बैकअप प्लान के रूप में उपयोग करना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता दोनों की विफलता है। यदि इसे समय रहते नहीं सुधारा गया, तो यह न केवल प्रशासनिक क्षमता को कमजोर करेगा, बल्कि युवाओं के बीच सिस्टम के प्रति विश्वास को भी खत्म कर देगा। आज सरकार, भर्ती एंजिनों और नीति-निर्माताओं के सामने एक सीधा प्रश्न खड़ा है— क्या वे एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जहाँ सीटें खाली रहें, संसाधन बर्बाद हों और योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाएँ? या वे एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं, जहाँ हर सीट भरे, हर अवसर का सही उपयोग हो और हर योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिले?

रोलिंग वेटलिस्ट + न्यूनतम सेवा प्रतिबद्धता + कूल-ऑफ नीति + पारदर्शी डेटा सिस्टम

अब आवश्यकता केवल इच्छाशक्ति की है। क्योंकि जब तक नीति नहीं बदलेगी, तब तक कट-ऑफ के उस पार खड़े लाखों युवाओं के लिए न्याय केवल एक सपना ही बना रहेगा।

—सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

अटल निश्चय से उपजे विराट संकल्प की बदौलत प्रगति के विकास पथ पर सवार राजस्थान



रामसिंह

विकसित भारत 2047 के गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए पीएमजीएसवाई महत्वपूर्ण बिन्दु भी है, साधन भी है। इस राज्य के क्रियान्वयन से पूर्व राज् के हजारों गांवों में हर मानसून में जन जीवन ठहर सा जाता था। पुराने और जर्जर पुल बाढ़ के पानी में डूब जाते थे, जिससे असीमित विद्यार्थी और किसान अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों जैसी सुविधाओं से कटते जाते थे। इसी जर्जरता को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असेंबल

गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत बन रखी। सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरूस्थलीय तथा आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी को बसावटों की सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर इसमें प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है।

इसी लक्ष्य की शक्ति में राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारागत 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किमी. सड़कों का निर्माण किया गया एवं 15983 बसावटों/गांवों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। प्रथम चरण में प्रदेश में लगभग 12086 करोड़ रुपये की लागत से 49 हजार 730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। इसके साथ ही 14043 किमी. सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चयनित थ्रू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया गया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि किसानों, कलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित संकेचिति स्थापित की जा सके। इस चरण में अब तक प्रदेश में 4 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 8 हजार 548 किमी. की 912 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 करवाया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

पीएम जेएनएम- इतिरि कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के</

उदयपुर : अनियंत्रित टैंकर ने हाइवे पर कई वाहनों को चपेट में लिया, बड़ा हादसा टला

बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, बाइक सवार युवक भी गंभीर घायल, नौ लोग हॉस्पिटल में भर्ती



हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को गाड़ियों से निकाला।



एक के बाद एक कई वाहन टैंकर में पिछे से टकरा गये।

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी पावर हाउस के पास गुरुवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहे एक टैंकर ने हाइवे पर देवारी पावर हाउस के पास अचानक अनियंत्रित होकर कई वाहनों को चपेट में ले लिया। इस दौरान पीछे आ रही कारें भी टैंकर से टकरा एक-दूसरे से भिड़ती चली गयीं। 10 से 12 कारें, ऑटो, टैपो और एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर चीख-पुकार मच गयी।

घटना की सूचना पर आसपास के लोग बचाव के लिए दौड़े। सूचना पर

पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों से घायलों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जबकि बाइक सवार युवक गंभीर घायल है, जिनमें नौ लोग हॉस्पिटल भर्ती हैं, बाकि क्षतिग्रस्त वाहन चालकों के चोटें आयी हैं, जो प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए। थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि देवारी पावर हाउस के सामने हाइवे पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहा एक टैंकर अचानक दलान पर अनियंत्रित हो गया, अनियंत्रित टैंकर ने आगे चल रहे कई वाहनों को चपेट में लिया। इस दौरान

■ पीछे आ रही कारें भी टैंकर से टकरा एक-दूसरे से भिड़ती चली गयीं, 10 से 12 कारें, ऑटो, टैपो और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं

■ देवारी पावर हाउस के सामने हाइवे पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहा एक टैंकर अचानक दलान पर अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों को चपेट में ले लिया

पीछे आ रही कारें भी टैंकर से टकरा एक-दूसरे से भिड़ती चली गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और कई लोग क्षतिग्रस्त वाहनों में फंस गए। पुलिस ने सभी

घायलों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां सुनील कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी डबोक, पूर्ण कुल्मी पुत्र कालू लाल निवासी मंगलवाड़, रमेश पुत्र जवेरा

निवासी रेबारियों का गुडा, अभिषेक शर्मा पुत्र खूबी लाल निवासी बड़गांव, डालूराम पुत्र सुरता, निवासी आवरीमाता, रेती स्टैण्ड, नारायण लाल पुत्र जय चंद कुल्मी, निवासी देवली, पीराना, अपिंत पालीवाल पुत्र रूप लाल निवासी देवली, मरमोत पुत्र ब्रिजकिशोर निवासी बदला रोड का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में गंभीर घायल अमजद खान पुत्र जमालुद्दीन निवासी बैरा तहसील वाली, जिला पाली को एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रथमदृष्टया टैंकर के ड्रेक फेल होने

या दलान पर टैंकर के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है। हॉस्पिटल में उपचारत घायलों और उनके परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि सभी वाहनों को मौके से हटाकर या साइड कर यातायात सुचारू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह देवारी हाइवे पर इसी जगह के पास एक कैमिकल टैंकर भी पलटा था। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को साइड करवा दिया था और फायरब्रिगेड की मदद से कैमिकल को सड़क से धो दिया गया था। इसके कुछ घंटों बाद ही यहां यह भीषण हादसा हो गया।

प्लॉट की चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग की गला काटकर हत्या

बीकानेर, (निसं)। चौकीदार की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। 70 साल का बुजुर्ग एक प्लॉट की चौकीदारी कर रहा था। उसने दो दिन पहले ही यहां चौकीदारी का काम शुरू किया था। मामला जयनारायण ब्यास कॉलोनी थाना की मदन विहार कॉलोनी का है।

■ पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल साक्ष्य जुटाये

जानकारी के अनुसार राहगीरों ने भंवरलाल रेगार (70) निवासी शिवबाड़ी का शव पड़े देखा और पुलिस को सूचना दी थी। अज्ञात हमलावरों ने भंवरलाल रेगार की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही सीओ अनुष्ठा कालिया और थानाधिकारी विक्रम तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की और

एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि जिस प्लॉट पर मृतक चौकीदारी कर रहा था, वह जैसलमेर निवासी कुंदन सिंह का है। भंवरलाल हाल ही में 30 मार्च को ही यहां काम पर लगा था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

अवैध पिस्टल के साथ यूपी का युवक गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। पुलिस अधीक्षक धर्मेश सिंह द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।

■ पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी

थानाधिकारी डॉ. नेहा राव ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाने गिरफ्तार के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम अहिंसा बंगलों के सामने 80 फीट रोड पर पहुंची। वहां पुलिस जाबो को देखकर एक युवक संदिग्ध अवस्था में भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर युवक को दबोक लिया। पकड़े गए युवक की पहचान शिवकुमार

भदोरिया (20) निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश हाल निवासी अजादनगर भीलवाड़ा के रूप में हुई है। जाबो द्वारा युवक को तलाशी लेने पर उसके पास एक देशी पिस्टल बरामद हुई। जांच करने पर पिस्टल अनलूड पाई गई जिसमें मैग्जीन लगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली है। आरोपी यह हथियार कहाँ से लाया था और इसे कैसे बेचने या किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इस संबंध में पुलिस गहनता से अनुसंधान कर रही है। पुलिस अब हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े का खुलासा

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वर्ष 2022 में आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मूल अभ्यर्थी ने किसी डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठकर परीक्षा दिलाई थी। इस पर एसओजी की तरफ से शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। मामले में अग्रिम तपत्ती की जा रही है। एसओजी ग्रुप यूनिट के एएसपी स्यामसुंदर विस्नोई ने यह रिपोर्ट दी है।

■ मूल अभ्यर्थी ने किसी डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठकर परीक्षा दिलाई थी

■ एसओजी की तरफ से शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल उपस्थिति पत्रक एवं ओएमआर शीट के अवलोकन में फोटो और हस्ताक्षरों में स्पष्ट भिन्नता पाई गई। प्रथम प्रश्न पत्र में हस्ताक्षर हिन्दी में तथा द्वितीय प्रश्न पत्र (हिन्दी विषय) में हस्ताक्षर अंग्रेजी में पाए गए। दोनों परीक्षाओं के दस्तावेजों में फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। अनुसंधान में यह

भी सामने आया कि दिनेश कुमार ने अपने परिचित मनोहर लाल निवासी सांभौर जिला जालोर के माध्यम से डमी अभ्यर्थी को व्यवस्था की थी। इसके लिए प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर फोटो व हस्ताक्षर बदलकर फर्जी एडमिट कार्ड तैयार किया गया। उक्त डमी अभ्यर्थी को जोधपुर के सरदारपुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा दिलाई गई।

प्रकरण में पूछताछ में पता लगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र हिन्दी की परीक्षा दिनेश कुमार ने स्वयं दी। पूछताछ में उसने यह स्वीकार भी किया कि प्रथम प्रश्न पत्र उसने स्वयं नहीं दिया था। यह परिवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी यूनिट अजमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट की तरफ से की जा रही है।

कोटा, (निसं)। युवक की हत्या के साढ़े छह साल पुराने मामले में महिला उल्कीडन न्यायालय क्रम-1 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मामले में दो महिलाओं सहित 12 जनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2018 को फरियादी जाहद हुसैन ने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसका मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू जो बोम्बे योजना में परिवार सहित रहता है, रिपोर्ट में कहा कि उसके मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का उसके पड़ोसी रमजानी के बीच बकरे के मामले को लेकर विवाद हो गया था। वह व उसका भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू तथा दो मित्र यशपाल व कालू उसके मामा के घर मिलने आये थे।

फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसका भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू व यशपाल दुकान पर कुछ सामान लेने गये, उसी समय बकरे की लड़ाई की रंजिश के चलते रमजानी ने अपने दो बेटे मुख्तार मोहम्मद, मुशताक मोहम्मद उर्फ भुरू, एवं शोयब, सद्दाम, जहीर, शाहरूख, मुबारिक व सात-आठ अन्य ने चाकू, लकड़ियां व धारदार हथियार लेकर एकराय होकर जान से मारने की नियत से उसके भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू पर हमला कर दिया। जहीर, शाहरूख व मुबारिक ने उसके भाई के उपर चाकू से ताबातोड़ वार किये। बीच बचाव में यशपाल को भी चोट आई, हमलावर

■ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराये

हमला कर मौके से फरार हो गये। रिपोर्ट में कहा कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू को उपचार के लिये निजि अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसके भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर हत्या के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस ने मामले में कार्यवाही व अनुसंधान करते हुए बोम्बे योजना निवासी रमजानी मोहम्मद (57), उसकी पत्नी फरजाना (43), दो बेटे मुशताक मोहम्मद उर्फ भुरू (29), मुख्तार मोहम्मद (31) एवं मुबारिक अली (26), लाडपुरा निवासी सद्दाम खान (32), किशोरपुरा निवासी जहीर खान (35), बोम्बे योजना निवासी शाहिन खानम (37), शाहरूख उर्फ लंगडा (26), नईमुद्दीन उर्फ शोयब (26), शाहदत (30) एवं लाडपुरा निवासी शाहरूख (32) को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

श्रीगंगानगर, (निसं)। प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। आरोपी ने पति पर सोते समय धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद पति की एक दिन पहले आरोपी प्रेमी के साथ बहस हुई थी। जिसके बाद महिला ने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी।

एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि बुधवार रात एक बजे सूचना मिली कि एक गांव में स्थित चौधरी ईट भट्टे पर दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घायल भादर सिंह, और अमरीक को रावला अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया। भादर सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि अमरीक सिंह को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी सतनाम अपने साथियों के साथ भादर सिंह के कमरे पर पहुंचा और मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया।

मृतक भादर सिंह के बड़े भाई वीर प्रताप सिंह ने बताया कि मेरे भाई भादर सिंह की पांच साल पहले मनप्रीत कौर से शादी हुई थी। दोनों की एक साल की बेटी है। भादर सिंह (मृतक) एक ईट भट्टे पर ट्रेक्टर चलाने का काम

■ पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद पति की एक दिन पहले आरोपी प्रेमी के साथ बहस हुई थी

करता था। इसी भट्टे पर सतनाम सिंह पुत्र बख्तावर सिंह भी काम करता था। आठ महीने पहले मनप्रीत और सतनाम सिंह के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया। वीर प्रताप को जब मनप्रीत के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उसे काफी समझाने की कोशिश की। मगर मनप्रीत ने सतनाम से मिलना बंद नहीं किया। एक महीने पहले मनप्रीत के मामा के साथ उसने फिर से समझाया, इस पर उसने अपनी गलती मान ली और आश्वासन दिया कि वह सतनाम से नहीं मिलेगी। पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर भादर सिंह का काफी तनाव में रहता था। कुछ दिन पहले ही मनप्रीत अपनी बेटी को लेकर पीहर खाजूवाला चली गईं।

वीरप्रताप ने बताया कि बुधवार को मनप्रीत से अवैध संबंधों को लेकर भादर का सतनाम से विवाद हुआ। इसके बाद मनप्रीत ने सतनाम को मेरे भाई भादर की हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद रात

1 बजे सतनाम सिंह, गुरदास सिंह, गुरमीत सिंह बावरी, गुरजेंट, गुरचरण सिंह ने एकराय होकर भट्टे पर अपने कमरे में सो रहे मेरे भाई भादर सिंह और उसके साथ अमरीक सिंह पर हमला कर दिया।

चौधरी ईट भट्टे के मालिक कुलदीप भाभू ने बताया कि ईट भट्टे पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने बताया कि बुधवार शाम भादर सिंह और सतनाम सिंह के बीच कहासुनी हुई थी। इस पर कुछ मजदूरों ने दोनों पक्षों से समझावश कर एक बार की मामले को शांत कर दिया। इसके सतनाम सिंह मौके से चला गया। बुधवार रात में भादर सिंह अपने डॉक्टर के ड्राइवर अमरीक सिंह (35) साथ ईट भट्टे पर बनी झुग्गी में सो रहा था। रात करीब एक बजे सतनाम सिंह अपने भाई और 2-3 अन्य लोगों के साथ उसकी झुग्गी में आया। इस के बाद लाठी, डंडों और गंडासी से सोरे भादर सिंह और अमरीक सिंह में ताबडतोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर जब बाकी लोग जाग गए तो आरोपी मौके से भाग निकले।

रावला एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि मृतक और घायलों के परिजनों के द्वारा अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट दी गई है। घायल अमरीक के बयान ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। नाबालिग से दुष्कर्म के लामभग 14 माह पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

विभिन्न लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 22 फरवरी 2025 को ग्रामीण के एक

■ पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया

थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा कि 21 फरवरी 2025 को उसकी छोटी बहन को दूध देने के लिए वह पड़ोसी युवक के घर गई थी, वहां

पर युवक ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामले में कार्यवाही व अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 28 दस्तावेज पेश किए गए।

युवक का शव मिला

टोंक, (निसं)। उनियारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को टोंक-सवाई माधोपुर नेशनल हाइवे की पुलिया के नीचे करीब डेढ़ फीट के पानी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे उसके दोनों पैर के अंगुठे प्लास्टिक की रस्सी से आपस में बंधे थे। सूचना मिलने के

■ शव को शिनाख्त के लिए उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया

बाद उनियारा डीएसपी आकांक्षा चौधरी मौके पर पहुंची और शव को शिनाख्त के लिए उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। डीएसपी आकांक्षा चौधरी ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिलने के बाद टोंक-सवाई माधोपुर नेशनल हाइवे-552 पर कामधेनु सर्किल और कोर्ट के बीच की बाईपास पर गलवा नगर की पुलिया के नीचे भरे पानी में एक युवक का शव मिला, इसके बाद उनियारा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की। इसके बाद शव को पानी से बाहर निकलवाया, जो दो दिन पुरानी लग रही है। बाहरी चोट के निशान नजर नहीं आए और न ही किसी से लड़ाई झगड़े में होने वाली चोट है। जिसके बाद उनियारा पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है।

अजमेर-ब्यावर नेशनल हाइवे पर बायोडीजल टैंकर में भीषण आग लगी



आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं। वहीं दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।



अजमेर, (कासं)। जिले के मांगलियाबास क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहा बायोडीजल से भरा एक टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगते ही टैंकर चालक और खलासी ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को तुरंत किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल गए। उनकी सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने

■ चालक और खलासी ने टैंकर को सड़क किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल गए

■ टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया

से टल गया। बताया जा रहा है कि टैंकर गुजरात से अजमेर की ओर आ रहा था। जानकारी के अनुसार हादसा अजमेर-ब्यावर नेशनल हाइवे-8 पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ।

सूचना मिलते ही मांगलियाबास थाना पुलिस और दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हाइवे पर यातायात रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया। हादसे के दौरान पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए सुलगते टैंकर के बेहद करीब से दुपहिया वाहनों पर निकालते हुए नजर आए। इस लापरवाही के चलते हाइवे के दोनों ओर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले में खेत पर काम कर रहे किसान पर एक पैथर ने हमला कर दिया। किसान को संघर्ष करता देख कुछ बंदरों ने पैथर पर अटक कर दिया और पैथर को वहां से भगाकर किसान की जान बचाई। इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि किसान की गृहार सुनकर महाबली ने अपनी वानर सेना भेजी। किसान भी हनुमानजी का भक्त है और गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव भी है।

जानकारी के अनुसार लोसिंग गांव निवासी वार्ड पंच तुलसीराम पाटीवाल (55) सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे। काम के बाद वे पास ही पेड़ की छाया में आराम करने बैठे तभी झाड़ियों

■ हमले में किसान के हाथ और पीठ पर मामूली खरोंचे आईं, आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुलसीराम को लोसिंग के अस्पताल पहुंचाया

में छिपे पैथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। पैथर ने उनकी गर्दन पर पंजा मार दिया, जिससे वे घबरा गए। तुलसीराम पालीवाल ने बताया कि अचानक हुए हमले के दौरान पास के पेड़ों पर बैठे बंदरों का झुंड शोर मचाते हुए नीचे आ गया और पैथर पर हमला

कर दिया। इसी बीच आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। बंदरों के हमले और लोगों को आता देखकर पैथर मौके से भाग निकला।

पीड़ित ने भावुक होकर बताया कि दो बंदर तो जैसे हनुमान जी बनकर आए और मेरी जान बचा ली। हमले में उनके हाथ और पीठ पर मामूली खरोंचे आईं हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुलसीराम को लोसिंग के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पैथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके।

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner
 Office ID - eephd1b1kn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473
 No.5966-85, Date: 27/03/2026

Notice Inviting Bid : 145-150/2025-26
 Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.04.2026 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 248.20 Lacs.
 UBN No. PHE2526WSOB15958, PHE2526WSOB15959, PHE2526WSOB15960, PHE2526WSOB15961, PHE2526WSOB15962, PHE2526WSOB15963
 जल सीमित है, इसकी बचत करें।
 (Aditya Shrivastava)
 Executive Engineer
 PHED, Distt (R) Div I Bikaner

DIPR/C/6330/2026

#RESILIENCE AND WIT

Marilyn Monroe and the Potato Sack Dress

One particularly sharp-tongued reporter criticized the gown, calling it 'cheap' and 'vulgar.' The reporter said that Monroe would look better in a 'potato sack.'



Marilyn Monroe, one of the most iconic and beloved actresses of the 20th century, was no stranger to public scrutiny. Her beauty, talent, and personal life were often the subject of intense media attention. However, one particular moment in Monroe's career highlighted not only the harshness of the media but also her ability to turn criticism into a clever, witty response.

Great Depression. During that time, women were often forced to make do with limited resources. Financial hardships meant that many families, particularly in rural America, had to resort to using potato sacks as makeshift clothing. The simplicity of the sack became a symbol of economic struggle, but also of resourcefulness and resilience.

In 1952, Marilyn attended the Photoplay Awards in a stunning red gown that accentuated her natural curves and glamorous allure. But, as was often the case with her, not everyone was enamored with her appearance. One particularly sharp-tongued reporter criticized the gown, calling it 'cheap' and 'vulgar.'

The 'potato sack' dress wasn't merely a piece of fabric but a symbol of strength and ingenuity. Monroe's use of this symbolism, combined with her unapologetic beauty, was an act of defiance against societal norms that reduced women to nothing more than their physical appearance or their ability to adhere to beauty standards set by the media.

Monroe's response also challenged the prevailing notion that beauty is defined by the price tag of a dress or the extravagance of a gown. The reporter even went so far as to say that Monroe would look better in a 'potato sack.'

Monroe's response also challenged the prevailing notion that beauty is defined by the price tag of a dress or the extravagance of a gown. The reporter even went so far as to say that Monroe would look better in a 'potato sack.'

Monroe, ever the savvy woman, turned this insult into a moment of both humor and brilliance. In a move that showcased her wit and grace, costume designer Jean Louis (who had worked with her on many films) designed a 'potato sack' dress as a playful and satirical response to the harsh criticism.

Monroe, ever the savvy woman, turned this insult into a moment of both humor and brilliance. In a move that showcased her wit and grace, costume designer Jean Louis (who had worked with her on many films) designed a 'potato sack' dress as a playful and satirical response to the harsh criticism.

The dress, created for the Academy Awards in 1953, was a clever comment on the absurdity of the reporter's insult. Monroe wore it with confidence, making a statement that beauty is not about the price tag or the label but about owning who you are, regardless of what the world thinks.

The dress, created for the Academy Awards in 1953, was a clever comment on the absurdity of the reporter's insult. Monroe wore it with confidence, making a statement that beauty is not about the price tag or the label but about owning who you are, regardless of what the world thinks.

The Great Depression and the Potato Sack as a Symbol

The 'potato sack' also had a deeper meaning, linked to the economic realities of the



The 'City of Witches'



Benevento is a little more than two hours by train from Rome.

The hunting and persecution of so-called witches was a practice that began to take root in Italy in the late 1300s, supervised and carried out in many ways by the Catholic Church. By 1542, Pope Paul III had created the Congregation of the Holy Office of the Inquisition, which tasked the church with criminalizing those who would speak against the faith. It was an amorphous crime because any misfortune to befall a person or town could be attributed to a witch, around 80 per cent of the people charged with witchcraft in early-modern Europe were women. Academics estimate that 22,000 to 33,000 witchcraft trials took place in Italy, with very few of these ending in capital punishment. Witch hunting appeared to largely come to an end by the 18th century.

• Kshema Jatuhkarna

Stepping off the train in the southern Italian city of Benevento is not a particularly haunting experience, in the sense that the air on a brisk October day yields nothing other than cloud cover and fog. That this is the so-called 'city of witches,' the site where women from all over the country might have flown in the middle of the night to dance around a famous walnut tree and to learn, effectively, how to be a witch, is not immediately apparent.

How Benevento became the city of witches

Some researchers argue that this southern Italian town, a little more than two hours by train from Rome, became known for its witches because of its unique political position. But to understand the root of the myth, we have to go back to 1428. The hunting and persecution of so-called witches was a practice that began to take root in Italy in the late 1300s, supervised and carried out in many ways by the Catholic Church. By 1542, Pope Paul III had created the Congregation of the Holy Office of the Inquisition, which tasked the church with criminalizing those who would speak against the faith. It was an amorphous crime because any misfortune to befall a person or town could be attributed to a witch, around 80 per cent of the people charged with witchcraft in early-modern Europe were women.

Where the witchiness of Benevento, a city of over 55,000, with a Roman theater and Arch of Trajan from ancient times, may be most felt is in the traditions of its residents, many of whom still hold close these passed-down superstitions. Depending on whom you ask, a curse of the evil eye must still be ward off with a specific ritual involving oil and water and a traditional prayer. Leaving a broom at your door is a good way to ensure that the local witches, known as the Janare, won't sneak under the threshold, they'll be too distracted counting the strands of straw. And if you wake to find that your horse's mane has been braided, a Janara must have taken it for a late-night ride.

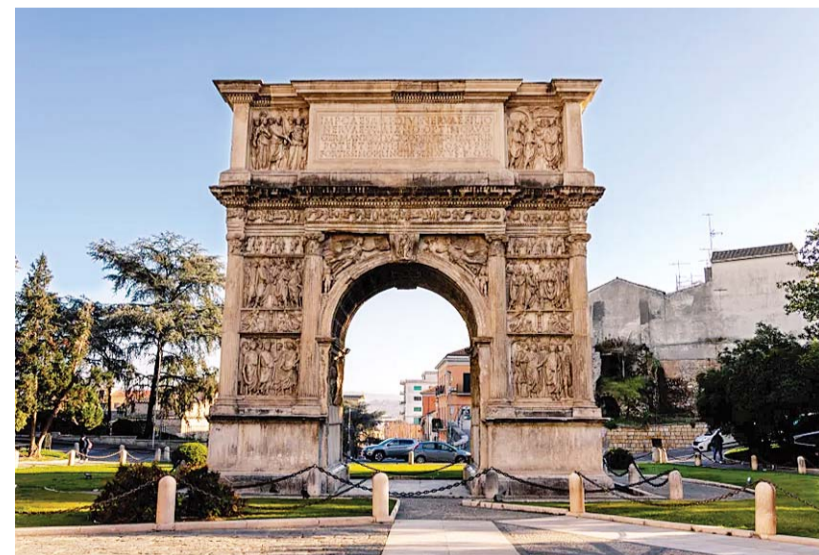
The first reference to Benevento as a place where witches gather dates to 1428. It comes from the transcripts of the trial of Matteuccia di Francesco, a 40-year-old woman, who was eventually sentenced to death and burned at the stake for witchcraft by the Franciscan Bernardino of Siena in the Umbrian town of Todi. From Matteuccia, we receive the famous formula, or incantation, that has since become inextricably associated with Benevento: "Unguento, unguento / mandame a la noce de Benivento, / supra aqua et supra ad vento / et supra ad omne maltempo."

Even now, when Maria Scarinzi, an anthropologist and head of education programs at Janua, Benevento's Museum of Witches, interviews older residents about their beliefs, she finds that they hesitate to share everything for fear of retribution.

"They still believe that if you name the Janara, she will come to your house at night and she will harm you in some way," Scarinzi says. "They still believe that if I tell you that I know the formula for getting rid of maggots, you will think that I am a Janara and you'll distance me from society."

They still believe that if you name the Janara, she will come to your house at night and she will harm you in some way," Scarinzi says. "They still believe that if I tell you that I know the formula for getting rid of maggots, you will think that I am a Janara and you'll distance me from society."

By 1640, local medical examiner Pietro Piperno penned his historical treatise on, among other things, the walnut tree of Benevento, explaining the origins of its supernatural powers. He claimed, according to Caruso, that it is not those from Benevento who participate in the late-night gathering of witches around the walnut tree, but people coming from elsewhere. In many ways, this only reinforced the link between Benevento and the witches.



The Arch of Trajan in Benevento dates back to 114 C.E.

Caruso's research is built on the idea that Benevento became the 'city of witches' because of its political isolation. Even when surrounded by the Romans, up until the third century B.C.E., the city once called Maleventum was ruled by the Samnites. It was eventually subsumed into the Romans' dominion, but after the fall of the Empire, by the sixth century C.E., the Lombards arrived, establishing Spoleto in Umbria and Benevento as their two southern duchies. What made Benevento unique is that, despite its

association with the Lombards, it managed to remain in large part independent from centralized control until the late 11th century C.E., when it was taken over by the papacy and largely stayed under papal control until becoming part of Italy in 1860. The fact that it had retained some sense of governing autonomy for so long sowed insecurity in the political leaders of the time.

"We must imagine Benevento as a very rich city, a papal city, an obligatory halfway point, you had to pass through Benevento," Scarinzi says. "We have to imagine it also as a kind of island in what was the Kingdom of Naples, difficult to conquer with all this wealth. So, how can I discredit someone? It's what we still do today. I speak ill of that person."

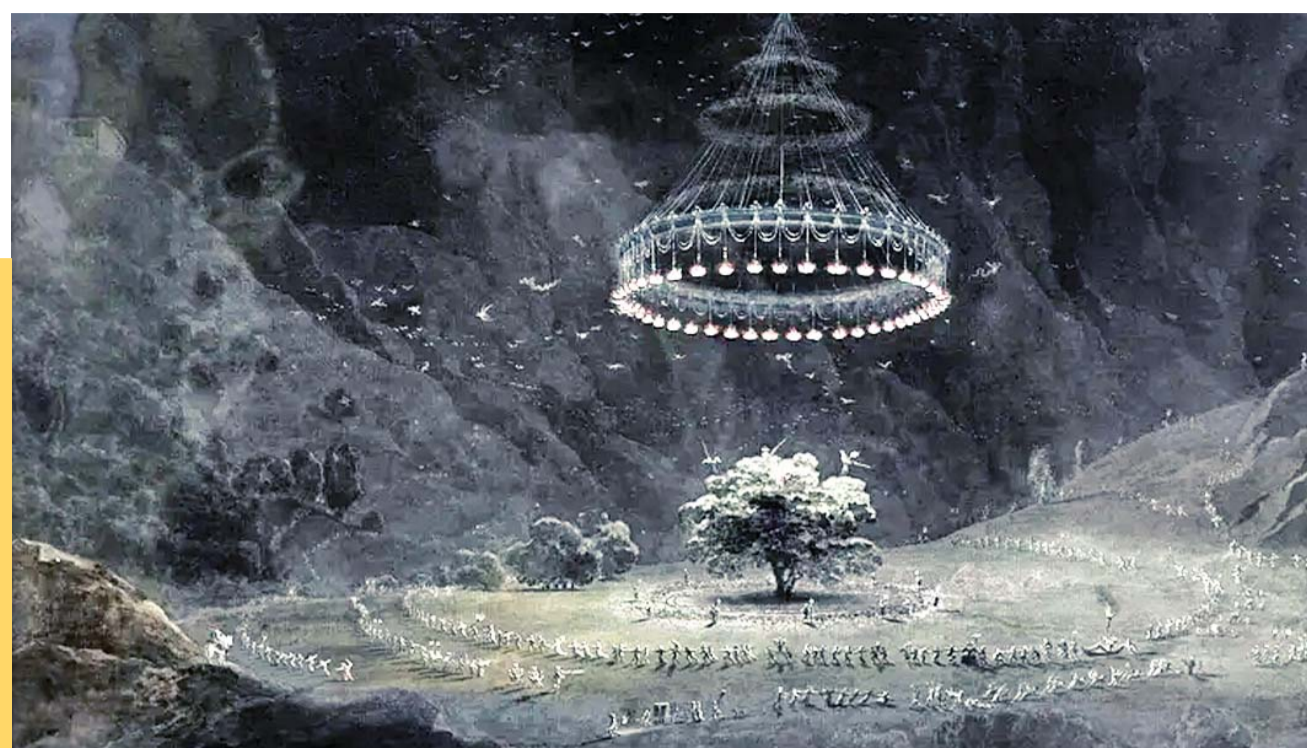
The targets of this abuse were generally local women known as healers, 'almost women of science,' Scarinzi says, or practitioners of what would today be called herbal medicine. These were women who knew the medicinal value of herbs like St. John's wort, lavender and dandelion, gleaned from information passed down to them through generations. "The negativity around these women was linked to the fact that people were afraid," Scarinzi says, "because they were women who had a power, which, in many cases, was medicine."

The modern-day legacy The Museum of Witches, located in the Palazzo Paolo V off the city's pedestrian Corso Garibaldi, is a testament to how the customs survive in the daily lives of its residents. For a couple of decades, anthropologists have been interviewing people about the history and customs of the larger province of Benevento. Part of this effort has been to talk with the elderly, mostly those 70 years and older, to preserve

#SUPERSTITION



The marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches.



The Walnut of Benevento (Sabbath of Witches), 1822-1826, by Giuseppe Pietro Bagetti Molteni & Motta.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

The Alberti family worked to make Liqueur Strega a symbol of Italy itself. In the 1920s, the brand enlisted well-known Futurist artist Fortunato Depero to create stylized advertisements. After the war, Guido Alberti helped to start the country's famous literary prize, Premio Strega, named in the brand's honour.

The museum opens with a short video punctuated by the voices of residents describing how the legend of the Janara has seeped into their way of life. Artifacts show the roots of rituals. A pair of small coffee cups tells the story of how a woman could entice the man of her dreams by serving a drop of her menstrual blood in his coffee.

"The belief was that, in the moment in which the woman made her proposal of love, the man had to, naturally, accept, otherwise he would die," Scarinzi says. "It was the Janara who gave the blood and the object a power."

A woman proposing rather than a man went against the customs of the time, but therein lay the power of the witch; she could rewrite the social order.

A 19th-century prayer, handwritten by a young child to protect her from any potential enemies, is on display. At the time, children would have donned amulets and charms to ward off evil. Another display explains how laundry hung outside to dry should be taken in by dusk for fear that evil spirits might be present after the setting of the sun.

The oral histories that the museum has collected shed more light on the behaviours that have grown out of these beliefs. Scarinzi learned that some local women have never been to a hairdresser, concerned that their hair would be kept and used against them in a spell.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

#SUPERSTITION



Witches of Benevento's cover.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

the superstitions and legends of the witches before they disappear. About 10 years ago, they had enough to open a museum.

Keeping the legend alive

Outside of the customs and superstitions ingrained in the culture of Benevento, there's a capitalist reason why the legend has survived: the Liqueur Strega, founded in 1860 by Giuseppe Alberti, who opened his bar in the center of Benevento.

American writer Johnny Marciano came to the town in 2002 after reading a brief reference to the witches in a guidebook on Campania, the region of Naples and Benevento. While he didn't leave with an immediate impression of the witches, the legend sparked him to write a two-page story on a town in which the children actually listened to their parents because of the mere threat of the Janare.

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

Strega means 'witch' in Italian. It didn't take long for Strega to become a symbol of Benevento, the marketing of the yellow-colored liqueur, made in part with saffron, juniper and mint and bearing a slightly sweet yet smooth taste, was indelibly linked to the city and its witches. The label bears an illustration of witches dancing around a walnut tree. Today, its store is the first thing you see when descending from the train station. Palma notes that, on bottles of the liqueur, the location is even written as 'near the train station,' because Benevento has long been considered an important junction that connected north and south.

Years later, that idea would become 'The Witches of Benevento,' a six-book children's series by Marciano and Sophie Blackall. In his research, Marciano was struck by the stories he heard residents recount 'with all sincerity.'

#HASRAT

The Love Story of Iqbal, Hasrat Jaipuri

Iqbal fell in love with a Hindu girl, Radha. She would often come to Jhakora of her home. And Iqbal would simply wait there



Iqbal, born in 1922 in Jaipur, came from a modest background. His early life was marked by a deep passion for poetry. Even as a young boy, Iqbal was known for his soulful expression through words, weaving emotions into his verses. His connection with poetry began to blossom in his teenage years, after he fell in love with Radha, Iqbal fell in love with a Hindu girl, Radha. She would often come to Jhakora of her home. And Iqbal would simply wait there. In their brief but intense relationship, Iqbal and Radha's love story faced enormous obstacles. They came from two vastly different cultural and religious backgrounds, Iqbal, a Muslim from a deeply spiritual and intellectual family, and Radha, a Hindu girl, rooted in the traditions of her people. At one point, he even worked as a bus conductor in Bombay (now Mumbai), hoping to find a better future.

including those from the world of cinema. **Meeting Prithviraj Kapoor and the First Steps into Bollywood**

The Iconic Song in 'Brahmachari'

It was at one of these Mushairas that Iqbal's life took a significant turn. Prithviraj Kapoor, the legendary actor and father of Raj Kapoor, attended a Mushaira where Iqbal recited his poetry. Kapoor was deeply impressed by Iqbal's verses and invited him to explore opportunities in Bollywood. This was a turning point for Iqbal, and he began his journey into the world of film music.

As Iqbal's (Hasrat Jaipuri's) fame grew, he continued to collaborate with Raj Kapoor and other renowned composers. One of his most famous works came in 1968, with the iconic song 'Main nashe mein hoon,' from the film *Brahmachari*. The song, composed by Shankar Jaikishan, was a playful yet emotionally charged piece, which became an anthem for many.

Throughout his career, Hasrat Jaipuri's pen captured the essence of longing and love. His words became an expression of a romantic idealism that resonated with millions. His songs reflected a tender side of romance, often invoking themes of separation, yearning, and hope.

The Big Break: 'Barsaat' and the Rise of Hasrat Jaipuri

Iqbal's first big break in Bollywood came when he was hired to write lyrics for the film *Barsaat* (1949), directed by Raj Kapoor. Raj Kapoor, impressed by Iqbal's work, entrusted him with several key songs for the film. This marked the beginning of a long and successful collaboration between Iqbal and Raj Kapoor.

Iqbal's Legacy and the Influence of Love in His Lyrics

Iqbal moved to Bombay, like many young dreamers, hoping to make a name for himself in the bustling city of opportunities. However, his start was far from glamorous. As a bus conductor, Iqbal lived a life far removed from the world of glamour and poetry that he dreamed of. He wrote his pain of separation with Radha in his verses and poetry.

Iqbal's breakthrough came when his poetic skills were recognized at Mushairas in Bombay. His pen name, Hasrat Jaipuri, became known in the literary world. His eloquent verses and passionate delivery captured the attention of several influential people in the city,

Throughout his career, Hasrat Jaipuri's pen captured the essence of longing and love. His words became an expression of a romantic idealism that resonated with millions. His songs reflected a tender side of romance, often invoking themes of separation, yearning, and hope.

The Move to Bombay and the Beginnings of a New Life

Iqbal's first big break in Bollywood came when he was hired to write lyrics for the film *Barsaat* (1949), directed by Raj Kapoor. Raj Kapoor, impressed by Iqbal's work, entrusted him with several key songs for the film. This marked the beginning of a long and successful collaboration between Iqbal and Raj Kapoor.

Iqbal's Legacy and the Influence of Love in His Lyrics

Iqbal moved to Bombay, like many young dreamers, hoping to make a name for himself in the bustling city of opportunities. However, his start was far from glamorous. As a bus conductor, Iqbal lived a life far removed from the world of glamour and poetry that he dreamed of. He wrote his pain of separation with Radha in his verses and poetry.

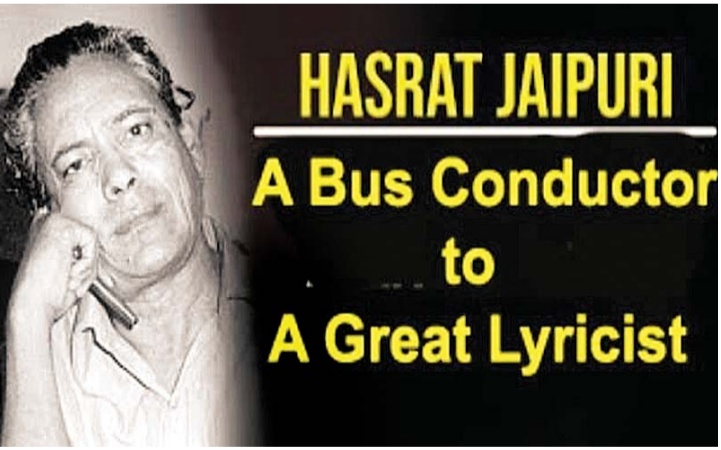
Iqbal's breakthrough came when his poetic skills were recognized at Mushairas in Bombay. His pen name, Hasrat Jaipuri, became known in the literary world. His eloquent verses and passionate delivery captured the attention of several influential people in the city,

Throughout his career, Hasrat Jaipuri's pen captured the essence of longing and love. His words became an expression of a romantic idealism that resonated with millions. His songs reflected a tender side of romance, often invoking themes of separation, yearning, and hope.

Iqbal moved to Bombay, like many young dreamers, hoping to make a name for himself in the bustling city of opportunities. However, his start was far from glamorous. As a bus conductor, Iqbal lived a life far removed from the world of glamour and poetry that he dreamed of. He wrote his pain of separation with Radha in his verses and poetry.

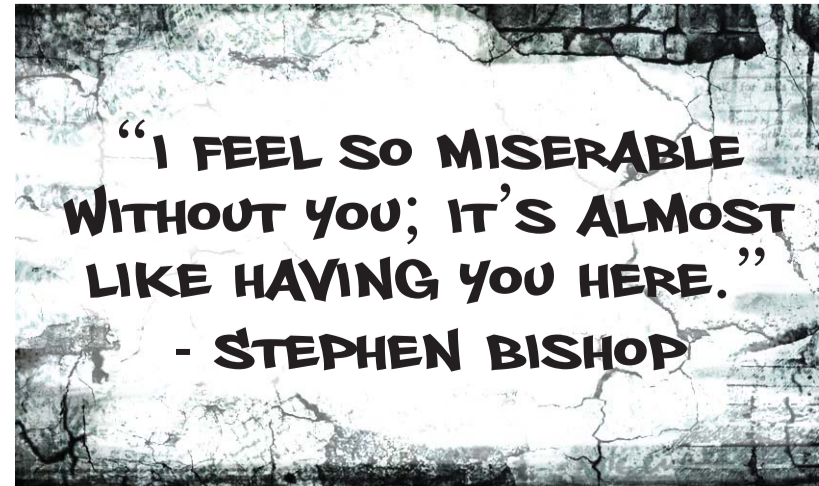
Iqbal's breakthrough came when his poetic skills were recognized at Mushairas in Bombay. His pen name, Hasrat Jaipuri, became known in the literary world. His eloquent verses and passionate delivery captured the attention of several influential people in the city,

Throughout his career, Hasrat Jaipuri's pen captured the essence of longing and love. His words became an expression of a romantic idealism that resonated with millions. His songs reflected a tender side of romance, often invoking themes of separation, yearning, and hope.



HASRAT JAIPURI
A Bus Conductor to A Great Lyricist

THE WALL

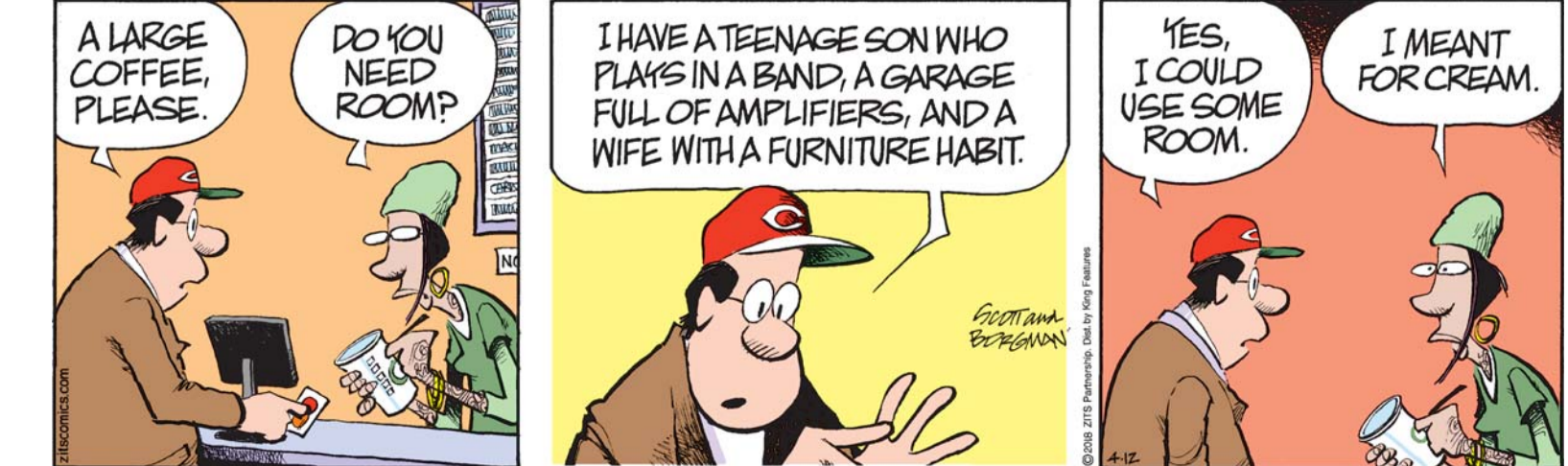


BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज्य के 17 लाख युवाओं का पंजीयन- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की

जयपुर, 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए। "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" देश की इसी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं को कोशल विकास, रोजगार से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को अवसर देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये नशा-मुक्ति की दिशा में भी गतिविधियाँ संचालित की जाएँ।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्ति, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा की।

"फिट राजस्थान, हिट राजस्थान" के विजन को हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पेरपलीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं से युवाओं के सपनों पर कुटाराघात हुआ। अब भती परीक्षाएँ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी

के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियों दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" युवाओं को सरकार से सीधे जोड़ने का सशक्त डिजिटल

माध्यम है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवा अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, जिससे विकसित

30 जून तक पेट्रोकेमिकल उत्पादों से कस्टम ड्यूटी हटाई

पश्चिम एशिया में जारी जंग के मद्देनजर सरकार ने बड़ी राहत दी

■ केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण में बताया कि भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन व कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर आयोजित होते हैं।

भारत के विजन को गति मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बने विकसित भारत यंग लीडर्स से संवाद भी किया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण एवं यंग लीडर्स उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच, पेट्रोकेमिकल उत्पादों का मुख्य रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों से अगले तीन महीने तक के लिए पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमत में होने वाली बेतहाशा वृद्धि से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है।

अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के दौरान केन्द्रसरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से फार्मास्यूटिकल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे उद्योगों को काफी फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी हटाने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत में गिरावट आएगी और आम आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।

इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेंजिन, यूरीथाइड टैरेप्सोलिक एसिड, मेथेनॉल, फिनॉल, टॉल्युन,

■ इन उत्पादों में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेंजिन, मेथेनॉल, अमोनिया, एथिलिन पॉलिमर्स आदि शामिल हैं।

एनहाइड्रस अमोनिया, एथिलीन पॉलिमर्स और कई तरह के फॉर्मिल्डहाइड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 30 जून तक के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने इन अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इंपोर्ट से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पश्चिमी एशिया में जियो-पॉलिटिकल टेंशन चरम पर पहुंचा हुआ है। इस टेंशन का असर दुनिया भर में अहम पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच चल रही लड़ाई के चलते वैश्विक स्प्लाई चैन को भी झटका लगा है, जिसकी वजह से इन उत्पादों की कीमत में भी तेजी आने लगी है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी हटाकर केन्द्र सरकार भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की लगातार स्प्लाई सुनिश्चित करना

चाहती है।

इस संबंध में बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी में इस झटके का उद्देश्य स्प्लाई को बनाए रखने और वैल्यू चैन में कीमतों में बड़ी तरोती को रोकना है। इस कदम से केन्द्र सरकार को यह उम्मीद थी है कि एंड कंज्यूमर्स के लिए कीमतों में स्थिरता आएगी, क्रायिक कच्चे माल की लागत में कमी से कंपनियों को उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई कीमतों का दबाव नहीं डालना पड़ेगा।

आईपैक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काम देख रही है। आईपैक से पहले प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान कुछ मिला है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार संभाल रही आई पैक नई दिल्ली, बंगलुरु और हैदराबाद के ऑफिस में छापेमारी की। बंगलुरु में आईपैक के डायरेक्ट ऋषिकान्त सिंह के आवास पर भी रेड हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक, कोयला तस्करी मामले की जांच के लिए आई पैक के ठिकानों को खंगाला गया है।

अदालती आदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोग अपने आप ही चुनाव के कार्यक्रम को 15 तारीख से आगे बढ़ाने का फैसला कैसे ले सकता है, जबकि इस संदर्भ में न तो अदालत में कोई आवेदन पेश किया गया है और न ही अदालत ने कोई अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता को भी अदालत में उपस्थित होने का आग्रह किया। महाअधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार कुछ ही दिनों में चुनाव के कार्यक्रम को 15 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने जा रही थी। परंतु आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम कैसे और किस प्रकार से तय

किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अदालत के समक्ष ऐसा कोई भी आवेदन पेश नहीं किया गया है। अदालत ने आगे कहा कि प्रदेश के चुनाव आयोग को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव स्वतः ही आगे कैसे बढ़ाया, जबकि अदालती आदेश इसके बिल्कुल विपरीत थे। इसके साथ ही, अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करा है।

मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ब्रिज पर अमेरिका का हमला

तेहरान, 02 अप्रैल। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाले एक 'बी1' हाईवे ब्रिज पर गुरुवार को हवाई हमला किया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी नुकसान हुआ है।

यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और

■ 3800 करोड़ रु. की लागत से बना यह पुल तेहरान को ईरान के उत्तरी भाग से जोड़ता है।

136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट करीब 400 मिलियन डॉलर में बना था।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आस सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूख से अलग है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया के ताजा संकट में भारत की कूटनीतिक परंपरा और कुशल बताते हुए कहा है कि इसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आस सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूख से अलग है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

होर्मुज़ स्ट्रेट पर ब्रिटेन में 60 देशों की मीटिंग

भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज़ संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेंट कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था।

मिसरी ने चर्चालु माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनिया भर के देशों के

■ भारत ने मीटिंग में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने अपने जांबाज़ नाविकों को खोया है।

सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने इंचिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है।

ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई बैठक में भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने

अपने जांबाज़ नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा।

वहीं, बैठक के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, होर्मुज़ से जहाजरानी सेवाओं को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा और इसके लिए समुद्री उद्योग साझेदारी के अलावा, सैन्य शक्ति और राजनयिक

गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक होगा। स्टार्मर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस अपील को स्पष्ट नकार चुके हैं कि ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों को होर्मुज़ खुलवाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहिए।

इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जलडमरूमध्य स्थिर नहीं रहेगा। वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियाँ कीं, जिसमें उन्होंने शीघ्र युद्धिरवाम का भी आन किया।

ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका को एयरस्पेस देने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ईरान और यूएस-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, कई देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे समय में अमेरिका को झटका लगा है। अब ऑस्ट्रिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

ऑस्ट्रिया ने ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशनों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल को अमेरिकी मांग टुकारा दी है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला देश के सख्त तटस्थता कानून के तहत लिया गया है।

ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कहा, हम जीत गए हैं

अमेरिका की जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने का दावा किया

■ ट्रंप ने कहा कि ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है।

क्या है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एफिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त

जोत हासिल की है। यह एक ऐसी जीत है, जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनकी हथियारों की फैक्टरियाँ तथा रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे रह गए हैं।

सात जजों को नौ घंटे बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के एक समूह ने न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जो एसआईआर से संबंधित जरूरी कार्य कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हर चीज "राजनैतिक" हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। सवाल यह है कि राज्य में बढ़ती अराजकता और हमलों के बावजूद केन्द्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है।

निकुंठ किस्म की हिंसा की इन घटनाओं के बावजूद, आरोप है कि ममता बनर्जी खुले मंचों से और उकसाने वाले बयान दे रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, ओबेसी, माकपा तथा भाजपा पर इन घटनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। बताया गया कि उन्होंने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, से अपील की कि जो भी उनके पास उपलब्ध हो, उसके साथ बाहर निकलें और एसआईआर

कार्य को रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारी माताएँ और बहनें चुप क्यों हैं?" और वादा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम नहीं होने दिया जाएगा।

ममता बनर्जी हर कदम पर गैर-जिम्मेदारी और उकसाने की राजनीति को बढ़ाती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर वे नहीं होतीं, तो बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) जीवित नहीं रहता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके बिना, यह समुदाय दूसरे समुदाय के हमलों का शिकार हो सकता है।

इसके बाद से वे किसी भी कीमत पर एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) कार्य को रोकने के लिए संगठित प्रयास करती नजर आई हैं। राज्य के शीर्ष राजनीतिक स्तर से दिए गए ऐसे बयानों के बाद लोगों में टकराव का माहौल बन गया है।

चार न्यायिक अधिकारी एसआईआर के तहत मतदाता सूची सुधार का काम कर रहे थे। इन

अधिकारियों को भीड़ ने उनके कार्यालय में घेरकर रोक लिया, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के आन के अनुरूप ही हुआ।

इन न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही राज्य प्रशासन और कलकत्ता उच्च न्यायालय को उस क्षेत्र में अपनी असुरक्षा के बारे में सूचित किया था, जहाँ वे कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यस्थल को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनकी मांग को राज्य प्रशासन तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं राज्य प्रशासन को सुरक्षा देने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि न्यायिक अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं।

पूरा कार्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया जा रहा है।

आप ने राघव चड्ढा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकसभा के 128 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, तब पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर से इनकार कर दिया था।

सूत्रों का कहना है कि कई मौकों पर चड्ढा सदन में बने रहे, जबकि आप सहित, विपक्ष के अन्य सदस्य वॉकआउट कर गए थे।

वर्ष 2025 के दिल्ली चुनावों में आप की हार के बाद चड्ढा ने पार्टी के भीतर तो लो प्रोफाइल रखा और केवल व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित रखा था।

बताया जाता है कि चड्ढा ने आप संस्थापक अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित शराब घोटाले में बर्ही होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में केजरीवाल द्वारा भाजपा के खिलाफ संबोधित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा में भी वे अनुपस्थित रहे। एक सूत्र ने कहा, "वे

अपना अलग एजेंडा चला रहे थे।"

हाल ही में चड्ढा ने भारत में पितृत्व अन्वेषण को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाकर सुर्खियाँ बटोरी थीं। उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर माता-पिता, दोनों को बधाई दी जाती है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी मुख्यतः माता पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि पालन-पोषण की जिम्मेदारियाँ समान रूप से साझा होनी चाहिए।

हवाई अड्डों पर महंगे खाने के खिलाफ उनकी पहल के चलते 'उड़ान यात्री कैफे' जैसे किफायती फूड काउंटर शुरू किए गए, जिससे यात्रियों को सस्ता खाना मिल सके। इसे उपभोक्ता अधिकारों की जीत बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के इस फैसले से नाराज चड्ढा भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनके भगवा दल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील देते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे और उनके अधिकारों को संरक्षित रखे।

खंडपीठ ने उनकी अपीलें पर पक्षकारों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में भती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से ऑपरेशन शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने भती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। ऐसे में इस स्तर पर भती परीक्षा स्थगित करने से व्यवस्थापक पैदा होगी। इसलिए भती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

'5037 बीघा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मकान तोड़ने की नौबत आ जायेगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी सी भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार को पूरी तरह से करना हाउसिंग बोर्ड को अपनी जमीन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिये और इसी में राज्य सरकार का और आम जनता का हित है। उन्होंने कहा कि 5037 बीघा जमीन में से वह जमीन, जिस पर अतिक्रमण नहीं है, उसे बचाने का प्रयास राज्य सरकार को पूरी तरह से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से ऑपरेशन शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने भती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। ऐसे में इस स्तर पर भती परीक्षा स्थगित करने से व्यवस्थापक पैदा होगी। इसलिए भती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

रोका जा सके। अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये एसएजी व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

बृद्धा से 80 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराध है। जिसमें कई स्तरों पर करीब ढाई दर्जन से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया है।

जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके खतों में पांच लाख रुपए आए थे और वह पीड़िता को दस लाख रुपए देकर राजीनामा कर रहा है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं अदालत में पेश होकर पीड़ित महिला ने कहा था कि उसे जांच एजेंसी के बयान नहीं दिला पा रही है और वह दबाव में राजीनामा कर रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अतः 27 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।